

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या-104/2005)

ताराचन्द कोरानी

—प्रार्थी—अपीलार्थी

बनाम

1. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान टेक्स बोर्ड, अजमेर।
3. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, रिजनल ऑफिस, अजमेर।

—अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.09.2023

उपस्थित :-

प्रार्थी—अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने ग्रेचुटी भुगतान आदेश दिनांक 05.10.2001 के द्वारा ग्रेचुटी राशि से 116832/- रुपये की वसुली किये जाने के आदेश को चुनौती दी है। अपीलार्थी की ओर से इस अपील में यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी राजस्व मण्डल अजमेर में शीघ्रलिपिक प्रथम श्रेणी के पद पर दिनांक 21.01.1979 को पदोन्नत हुआ था। अपीलार्थी को वेतन-श्रृंखला 450-770 के स्थान पर 550-1010 स्वीकृत की गई थी और अपीलार्थी परिवर्तित वेतन-श्रृंखला में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26ए के अंतर्गत लाभ देते हुए वेतन स्थिरीकरण किया गया था तथा अपीलार्थी के साथ कुछ अन्य शीघ्रलिपिकों को भी इसी प्रकार से लाभ दिया गया था। वेतन स्थिरीकरण का लाभ देय मानते हुए अपीलार्थी को अपीलार्थी को भुगतान किया गया था। बाद में प्रत्यर्थी विभाग ने यह माना कि अपीलार्थी ने नियम-26ए के अनुसार लाभ दो बार प्राप्त किया है। इस आधार पर अपीलार्थी से वसुली की गई थी।
2. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2001 को हुई है। इसके पश्चात अपीलार्थी से ग्रेचुटी भुगतान आदेश 30.12.2001 के जरिये वसुली की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है:-

State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be

that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

3. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से सेवानिवृत्ति के पश्चात वसुली किया जाना उचित नहीं है। परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी से जिस राशि 116832/- की वसुली की गई है, वह अपीलार्थी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से लौटाई जाये। इस आदेश की पालना 3 माह में की जायें।
4. रजिस्ट्रार को निर्देश दिये जाते हैं कि इस आदेश की पालना हेतु इस आदेश की प्रति संबंधित विभाग में प्रेषित करें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)